









# अमेरिका को हथियार-बैटरी बनाने वाले खनिज देगा यूक्रेन

जंग में मिली मदद के बदले डील करेंगे जेलेंस्की; ट्रम्प ने फंडिंग रोकने की घमकी दी थी

एजेंसी

वॉशिंगटन/कीवी, यूक्रेन, अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल (दुर्लभ खनिज) देने पर राजी हो गया है। यूक्रेन और अमेरिका दोनों देशों के अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। वहाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दाव किया है कि जेलेंस्की इस डील पर साझ करने के लिए शुक्रवार को अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। ट्रम्प करीब 1 महीने से

यूक्रेन सरकार पर अमेरिका को दुर्लभ खनिज देने को लेकर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना था कि यदि यूक्रेन को अमेरिकी मदद चाहिए तो उसे 500 विलियन डॉलर के दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे। उन्होंने जेलेंस्की को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका यूक्रेन को और मदद देना बंद कर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के साथ नई खनिज डील में अमेरिका ने 500 विलियन डॉलर के खनिज की



मांग छोड़ दी है। हालांकि, उसने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी देने से भी इनकार कर

दिया है। अमेरिकी अधिकारी इसका विरोध कर रहे थे। यूक्रेन डील के बदले में अमेरिका से सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा था। सोनेनक की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका दुर्लभ खनिज के बदले यूक्रेन के री-डेवलपमेंट (रिपबिकास) में मदद करेगा। दुर्लभ खनिजों की गोलबल सफ्टलैंड चैन में फिलहाल चीन सरबंसे बड़ा प्लेयर है। माझिंग टेकोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया के 69% दुर्लभ खनिजों का उत्पादन करता है, जबकि

लिया है। इन प्रांतों में यूक्रेन के कुल खनिज भंडार का 53% हिस्सा है, जिसकी मांग द्विलियन पाउंड यानी 660 लाख करोड़ रुपए हैं। इस पर उत्पन्न का सिंटरेल 2022 से कर्जाहा। यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मटेरियल के लिए चीन पर निर्भय है। अमेरिका को दोबारा यूक्रेन बनाने की बाबा करने वाले द्रम्प के लिए ये चिंता की बात है। इससे अमेरिका का आर्थिक और सैन्य मोर्चे 5% है। इसमें ग्रेफाइट का लागभग 19 मिलियन टन भंडार शामिल है। इसके पर दांव कमज़ोर पड़ सकता है। यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेत्स्क, जापोरिया और खर्स्तान पर रुस ने कब्जा कर

## सैलरी नहीं मिलने पर ओमान से नाव लेकर भागे भारतीय जीपीएस की मदद से 3000के एम का समुद्री सफर तय किया, तीनों को कोस्ट गार्ड ने पकड़ा

एजेंसी

मस्कट, ओमान में काम कर रहे तीन भारतीय सैलरी नमिनों से परेशन होकर भारत के लिए भाग निकले। देश वापस लौटने के लिए उन्होंने समुद्र का रास्ता चुना और एक नाव चुना ली। उन्होंने नाव के जरिए 3000 किमी का सफर भी तय कर लिया था, लेकिन 6 दिन बाद भारतीय कोस्टगार्ड ने उन्हें कार्रांक के उड़ूपी तरफ के पास पकड़ लिया गया। तीनों को सोमवार को उड़ूपी की आदालत में पेश किया गया था और जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस घटना की जानकारी अब सामने आई है। जेम्स फ्रैंकलिन और डेरोज अल्फांसो (38) तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तीनों



ओमान में एक मछली पकड़ने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। यहाँ उन्हें इसमें बोर्डर के रहने वाले हैं।

समय पर सैलरी नहीं मिल रही थी और उन्हें परेशन किया जा रहा था। ऐसे में तीनों ने घर वापस लौटने का मन बनाया। लेकिन, ओमान की कंपनी ने इन लोगों का पासपोर्ट जब तक कर लिया था, इसलिए इनके पास घर लौटने के लिए समुद्र के रास्ते अनें के अलावा कोई जरिया नहीं था। तीनों एक मछली पकड़ने वाली नाव लेकर जल्दी कर लिया। तीनों 17 फरवरी को दोपहर 3 बजे अपान के उड़ूपी हिस्से में दुकान बंदरगाह से निकले। 6 दिन का सफर तरफ कर 23 फरवरी को उड़ूपी के सेंट मैरी आईलैंड के पास नाव से भारतीय जलक्षेत्र में दाखिल हुए। ओमान की नाव देखकर एक लोकल मछुआरे ने इस बारे में तटीय सुरक्षा पुलिस को किया है।

## अमेरिकी नागरिकता देने के लिए 5 गुना वसूलेंगे ट्रम्प

44 करोड़ में सिटिजनशिप देंगे, 2 हफ्ते में शुरू होगा गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम

एजेंसी

वॉशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की नागरिकता देने के बदले 5 गुना ज्यादा पैसा बसूल करने वाले हैं। ट्रम्प ने मंगलवार को गोल्ड कार्ड नाम से एक नींवी ग्राम्यान्वय को सरकार द्वारा दिए गए 5 मिलियन डॉलर (44 करोड़ भारतीय रुपए) में खरीदा जा सकता है। ट्रम्प ने इसे अमेरिकी नागरिकता के लिए-इन्वी-5 वीजा प्रोग्राम सबसे असान रास्ता है। इसके लिए लोगों को 1 मिलियन डॉलर (करीब 8.75 करोड़ रुपए) देने



होते हैं। ट्रम्प ने कहा कि यह वीजा कार्ड अमेरिकी नागरिकता के रास्ते खोलेगा। इसे खरीदकर तेज़ अमेरिका का एगेंट और यहाँ बहुत ज्यादा टैक्स भरेंगे। उन्होंने दाव किया कि यह प्रोग्राम बहुत सफल होगा और इससे राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान जल्द हो सकता है। ट्रम्प ने मंगलवार को वीजा प्रोग्राम से जुड़े एकजीकीवीट ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए कहा कि गोल्ड वीजा कार्ड नागरिकों के लिए उपकार होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के 2 हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि नई योजना के बारे में

विस्तार से जानकारी जल्द ही दी जाएगी। इस दौरान उनके साथ कॉर्मिशिल सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक भी जाहजूदी थी। उन्होंने कहा कि नए वीजा प्रोग्राम से देश में निवेश बढ़ेगा, इसके साथ ही ईबी-5 से जुड़ी धोखाधड़ी रुकेगी और नौकरशाही पर लगाम लगेगी। अमेरिका में स्थानी तौर पर रहने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत होती है। इसके लिए ईबी-1, ईबी-2, ईबी-3, ईबी-4 वीजा प्रोग्राम हैं, लेकिन ईबी-5 वीजा प्रोग्राम सबसे ज्यादा बेहतर है। यह 1990 से लगू है। इसमें शब्द किसी रोजार देने वाले नियोक्ता से नहीं बदले होते हैं और अमेरिका में कहीं भी रहकर काम या फिर पढ़ाई कर सकते हैं।

## 'दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना सही नहीं केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर दी। आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए लोगों को 1 अप्रैल से अपारिवारिकों के लिए लगाना चाहिए।

हलफनामे में किया गया था, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक हलफनामा दायर कर दी गई थी। हलफनामे में कहा गया है, यह सवाल कि आजीवन प्रतिबंध लगाना उपयुक्त होगा या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के मांग की गई है। सरकार ने कहा कि अयोग्यता की अवधिविधायी नीति के दायरों में आती है। यह दाव 2016 में उपर्युक्त समय तक सीमित कर, रोकाल आपारिवारिक नागरिकों के लिए लगाना चाहिए।

हलफनामे में किया गया था, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत, अयोग्यता की अवधि दोपसिद्धि की तारीख से छह साल की तारीख के व्यापक समय से संसद को विधायी विकल्प द्वारा दोपसिद्धि की तारीख से छह साल के बीच तक रहनी चाहिए। यह सवाल कि दोपसिद्धि की तारीख से छह साल तक रहनी चाहिए। यह सवाल के बारे में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत, अयोग्यता की अवधि दोपसिद्धि की तारीख से छह साल की तारीख के व्यापक समय से संसद को विधायी विकल्प द्वारा दोपसिद्धि की तारीख से छह साल तक रहनी चाहिए। यह सवाल के बारे में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत, अयोग्यता की अवधि दोपसिद्धि की तारीख से छह साल की तारीख के व्यापक समय से संसद को विधायी विकल्प द्वारा दोपसिद्धि की तारीख से छह साल तक रहनी चाहिए।

हलफनामे में कहा गया था, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत, अयोग्यता की अवधि दोपसिद्धि की तारीख से छह साल की तारीख के व्यापक समय से संसद को विधायी विकल्प द्वारा दोपसिद्धि की तारीख से छह साल तक रहनी चाहिए। यह सवाल के बारे में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत, अयोग्यता की अवधि दोपसिद्धि की तारीख से छह साल की तारीख के व्यापक समय से संसद को विधायी विकल्प द्वारा दोपसिद्धि की तारीख से छह साल तक रहनी चाहिए।

हलफनामे में कहा गया था, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत, अयोग्यता की अवधि दोपसिद्धि की तारीख से छह साल की तारीख के व्यापक समय से संसद को विधायी विकल्प द्वारा दोपसिद्धि की तारीख से छह साल तक रहनी चाहिए। यह सवाल के बारे में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत, अयोग्यता की अवधि दोपसिद्धि की तारीख से छह साल की तारीख के व्यापक समय से संसद को विधायी विकल्प द्वारा दोपसिद्धि की तारीख से छह साल तक रहनी चाहिए।

भारत ने अपील की कहाँ दोपसिद्धि की तारीख से छह साल की तारीख के व्यापक समय से संसद को विधायी विकल्प द्वारा दोपसिद्धि की तारीख से छह साल तक रहनी चाहिए।

